अमृत तुल्य हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित, आओं इसके संरक्षण का संकल्प लें और फिर मनाएं अमृत महोत्सव

दैनिक अनोखा तीर की पाक्षिक प्रस्तुति...

FOLLOW US ON: Anokha Teer Harda @anokhateer

तपती धरती

पृष्ठ-8 | हरदा- मंगलवार 15 अगस्त 2023 | www. anokhateer.com

पर्यावरण संरक्षण से ही अमृत महोत्सव की सार्थकता

आज हम देश की आजादी का 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव दौरान हमने अपने अतीत और वर्तमान की समीक्षा भी हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए करने का प्रयास किया है। हमने अपने भौतिक विकास की अंधी दौड़ में क्या खोया और क्या पाया इस विषय पर भी गंभीरता से आंकलन किया है। बेशक आजादी के इन 75 वर्षों में हमने उपलब्धियों के पहाड़ खड़े कर दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। लेकिन इस दौरान हमने प्रकृति के साथ सर्वाधिक खिलवाड़ भी किया है। हमने प्रकृति का दोहन नहीं अपितु शोषण किया है। यह केवल भारत ने ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी विकास की अंधी दौड़ के चलते सभी दूर किया गया। जिसके दुष्परिणाम भी आज दुनिया के सामने देखने को मिल रहें हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से पूरी दुनिया चिंतित है। हम अपने देश की आजादी के 75 सालों का लेखा-जोखा करें तो पर्यावरण के मामले में हम फिसड्डी ही साबित होते हैं। क्या है हमारे पर्यावरण की हालत?

देश में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर धूमधाम से 75 सप्ताह का 'अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। लेकिन आजादी के बाद की पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा लगभग नगण्य रही। परंतु यह इस अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए इसे अमृत महोत्सव वर्ष का मुख्य हिस्सा भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने के उद्देश्य से मिशन लाइफ की शुरुआत करते हुए इससे आम लोगों को सीधे जोड़ने का प्रयास किया है। मिशन लाइफ जलवायु परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए सामाजिक संरचना की ताकत का उपयोग कर है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाना हैं। हमने दुनिया के समक्ष अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में ठोस कदम उठाना भी शुरू कर दिया है।

पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना होगा

लेकिन अगर हम अपने बीते 75 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी दाल काफी पतली रही है। पर्यावरण के सभी भाग- हवा, पानी, भूमि, जंगल एवं जैव-विविधता पर इन 75 वर्षों में काफी विपरीत प्रभाव हुआ है। सभी जीवों के जीने के लिए आवश्यक हवा में इतना प्रदूषण फैला कि वर्ष 2020 में हमारा देश विश्व के पांच सर्वाधिक प्रदूषित देशों में शामिल हो गया। स्विट्जरलैंड की फर्म 'एक्यू एअर' की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 63 हमारे देश के रहे। मुरादाबाद, कोलकाता, दिल्ली, आसनसोल व जयपुर ज्यादा प्रदूषित बताए गये। 'क्लाइमेट ट्रेंड' की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरप्रदेश की 99.4 प्रतिशत आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। पिछले 20 वर्षों में (1990 से 2019) वायु-प्रदूषण में 115 प्रतिशत की वृद्धि का आंकलन किया गया है। देश के 200 शहरों में वायु-प्रदूषण निर्धारित स्तर से अधिक है एवं 50 शहरों की हालत ज्यादा खराब है। देश के 88 में से 75 औद्योगिक क्षेत्र भी ज्यादा प्रदूषित हैं। 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' में हमारा देश वर्ष 2022 में अंतिम स्थान 180 पर बताया गया। जबकि वर्ष 2020 में 168 वें स्थान पर था। यह अध्ययन 'येल' व 'कोलम्बिया विश्वविद्यालय' तथा 'अर्थ इंस्टीट्यूट' द्वारा किया गया था। इस वर्ष के प्रारंभ में जारी 'एअर-क्वालिटी-लाईफ-इंडेक्स रिपोर्ट' के अनुसार देश में ऐसी एक भी जगह नहीं है जो 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के वायु-प्रदूषण के मानकों पर खरी उतरे। वायु-प्रदूषण के प्रभाव से भारतीयों की औसत उम्र भी लगभग 10 वर्ष घट रही है। दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद विश्व के अधिक ध्वनि-प्रदूषण वाले शहरों में शामिल हैं। उत्तरप्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक शोर वाला शहर बताया गया है।

जीवन देने वाला जल भी जानलेवा हो गया है। 'नीति आयोग' के 'जल प्रबंधन सूचकांक' (2018) के अनुसार देश का 70 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है एवं 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल' के अनुसार देश की 521 नदियों में से 351 काफी प्रदूषित हैं। 'राष्ट्रीय-स्वच्छ-गंगा-मिशन' की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 97 स्थानों पर जहां गंगाजल की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया, वहां का पानी आचमन लायक भी नहीं है। देश की कई बारहमासी या सदानीरा नदियां मौसमी बन गयी हैं। कृषि प्रधान देश में मिट्टी के हालात भी ठीक नहीं हैं। 15 करोड़ हेक्टर कृषि भूमि में से लगभग 12 करोड़ में पैदावार घट रही है। पशुधन भी कम हो रहा है। देश के कुल भौगोलिक भूभाग का लगभग 25 प्रतिशत रेगिस्तान की गिरफ्त में है। वन विनाश एवं कुछ अन्य कारणों से राजस्थान का रेगिस्तान भी दिल्ली एवं मध्यप्रदेश के मालवा की ओर बढ़ रहा है।

■ प्रहलाद शर्मा
संपादक

पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन भी भू-भाग के 33 प्रतिशत पर न होकर 21-22 प्रतिशत पर ही सिकुड़ गए हैं। इनमें भी सघन, मध्यम व छितरे वन क्रमशः 2, 10 एवं 9 प्रतिशत ही हैं। पिछले वर्षों में वनों में आग लगने की घटनाएं भी काफी बढ़ी हैं। वन क्षेत्रों में 80 प्रतिशत जैव-विविधता पायी जाती है, परंतु वन क्षेत्र घटने से 20 प्रतिशत जंगली पेड़-पौधे एवं जीवों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।

पिछले 75 वर्षों में देश में पर्यावरण से जुड़े कई नियम-कानून लागू किये गये। अलग से 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण' (एनजीटी) का गठन भी किया गया। परंतु इसके कोई सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक परिणाम नहीं आये। 'एनजीटी' ने कुछ प्रकरणों में जुर्माना लगाया एवं कई स्थानों पर उसके निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया। देश में सौर व पवन ऊर्जा का उपयोग जरूर बढ़ा है। टायगर एवं कुछ अन्य प्रोजेक्ट के साथ 'राष्ट्रीय उद्यान,' 'वन्यजीव अभ्यारण्य,' 'जैव-मंडल सुरक्षा-स्थल' एवं 'जीन बैंक' भी स्थापित किये गये हैं। इन सारे प्रयासों के साथ आजादी के इस 'अमृत महोत्सव' में पर्यावरण संरक्षण को प्रमुखता प्रदान करते हुए इसे एक जन आंदोलन बनाने की पहल की जा रही है जो समय की अहम मांग भी है।

आजादी के अमृत महोत्सव काल में आजादी की इस वर्षगांठ पर हम संकल्प लें कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव में हमारे जल-स्त्रोत साफ-सुथरे हों, शहरों व गांवों की हवा शुद्ध हो, शोर कम हो, कचरे के पहाड़ न बनें, पर्वत- मालाएं हरी-भरी हों, वन क्षेत्र का विस्तार एवं समुद्री तटों का सिकुड़ना समाप्त हो, जैव-विविधता बरकरार रहे एवं उसका विस्तार हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो लक्ष्य भारत के लिए वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का रखा है उसे हम निर्धारित समय से पहले पूरा करते हुए दुनिया के समक्ष मिशाल कायम करें। तभी हम इस तपती धरती पर जीवन को सुरक्षित रख पायेंगे। वरना चंद सांसों के लिए आक्सीजन की मारा मारी का दृश्य हम कोरोना काल में देख और भोग चुके हैं।

ROOPAI

ओजोन क्षरण से हुआ तापमान अतितृप्त
दूषित है पर्यावरण
जीवन है अभिशप्त

आत्मनिर्भर कृषक, आत्मनिर्भर कृषि
आम के आम गुठलियों के दाम

गौरीशंकर मुकाती
एम.डी.

संजय चौधरी
डायरेक्टर

संजय चौधरी
डायरेक्टर

ओमप्रकाश राठौर
एकाउंटेंट तीखड़

हरिओम यावड़ा
तीखड़

नीतू शर्मा
हरदा

स्वतंत्रता दिवस
की समस्त क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं

पर्यावरण संरक्षण के साथ वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण के माध्यम से मिट्टी कटाव रोकते हुए मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को सदा नीरा बनाएं रखने की पहल के साथ नर्मदांचल में किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य

रूपई एग्री फॉरेस्ट प्रा.लि. हरदा

शहरीकरण और औद्योगीकरण की बेतहाशा वृद्धि ने न केवल पर्यावरणीय समस्या को जन्म दिया है, अपितु अब तो पानी सर के ऊपर से जाने लगा है। समस्या जटिल बन कर नासूर बन चुकी है। आधुनिक समय का सबसे प्रासंगिक और विवादित मुद्दा पर्यावरण समस्या है। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग मानव जनित समस्या है। जो कुछ गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन की वजह से होता है।

कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पदचिन्ह

■ सुनीता फड़नीस
पर्यावरण चिंतक एवं
सेवानिवृत प्राध्यापक इंदौर

'कार्बन फुट प्रिंट' का अर्थ किसी एक व्यक्ति, संस्था या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन है, जो ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। मानव के सभी क्रियाकलाप, खानपान, कपड़े, वाहन से आना-जाना मिलकर 'कार्बनफुट प्रिंट' का कारण बनते हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है- जो भी कार्य मानव करता है, हर एक के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन सभी कार्यों में CO2 गैस निकलती है। जो धरती को गर्म करती रहती है।

हम हर दिन, हर महीने या हर वर्ष में जितनी CO2 पैदा करते हैं। वह हमारा 'कार्बन फुटप्रिंट' होता है। इसे न्यूनतम रखकर ही धरती को जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से बचाया जा सकता है ।

'कार्बन फुटप्रिंट' को आमतौर पर वजन के माप से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिवर्ष, प्रति टन के बराबर या मैट्रिक टन में भी प्रदर्शित करते हैं ।

ग्रीन हाउस गैस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली गैसें:- 1. कार्बन डाइऑक्साइड 2. मीथेन 3. नाइट्रस ऑक्साइड 4. हाइड्रो फ्लोरो कार्बन 5. हाइड्रो क्लोरो कार्बन 6.सल्फर हेक्साफ्लोराइड

ये सभी छः गैसें 'कार्बन फुटप्रिंट' मानी जाती है। इनमें से हर गैस का उत्सर्जन 'कार्बन फुटप्रिंट' के रूप में गिना जाता है। जब कोई कार चलती है, तो यह समझना आसान है कि इसमें कार्बन का उत्सर्जन हुआ होगा। लेकिन जब कोई साइकिल चलती हैं, तो इसमें कार्बन उत्सर्जन कैसे होता है? इन तीनों गतिविधियों में 'कार्बन फुटप्रिंट' है। यद्यपि साइकिल स्वयं कार्बन उत्सर्जित नहीं करती पर इसके निर्माण में तथा निर्माण स्थल से ट्रक द्वारा किसी स्टोर में पहुँचाने तक में भी कार्बन उत्सर्जित होता है। सोफे पर बैठकर समाचार पत्र या पुस्तक पढ़ने से या कागज में कुछ लिखने पर भी 'कार्बन फुटप्रिंट' होता है क्योंकि पुस्तक और पेपर का भी निर्माण किया गया होता है और वहाँ से वह किसी स्थानीय स्टोर में बेचने हेतु लाए जाते हैं या किसी गाड़ी से घर-घर पहुँचाए जाते हैं।

'कार्बन फुटप्रिंट' दो प्रकार से समझाए जा सकते हैं :-

'प्राथमिक कार्बन फुटप्रिंट' उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर किसी व्यक्ति का सीधा नियंत्रण होता है।

'द्वितीयक कार्बन फुटप्रिंट' : किसी व्यक्ति के 'कार्बन फुटप्रिंट' के शेष भाग को द्वितीयक कहा जाता है। यह वस्तुओं और सेवाओं की खपत से जुड़े कार्बन उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करता है।

कार्बन फुटप्रिंट ज्ञात करने की विधि

इसके लिए लाइफ साइकिल एसेसमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी व्यक्ति और औद्योगिक इकाई द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को जोड़ा जाता है। साधारण तौर पर 'कार्बन फुटप्रिंट' को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है, क्योंकि अन्य गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करीब -करीब कार्बन डाइऑक्साइड जितना ही होता है।

विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन चीन और अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इनका 'कार्बन फुटप्रिंट' सबसे बड़ा होता है। विकसित देशों की साधन संपन्न जीवन शैली, इसके लिए उपयुक्त विभिन्न विलासिता के उपकरणों का निरंतर उपयोग के कारण ऊर्जा खपत अधिक होती है और इनका 'कार्बन फुटप्रिंट' बड़ा होता जाता है। कम विकसित देशों में निर्धनता और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इनका 'कार्बन फुटप्रिंट' का मान कम होता है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि जहाँ तक हो सके हमें हमारे 'कार्बन फुटप्रिंट' को छोटे से छोटा रखना है। यही हमारा पर्यावरण का संरक्षण करने की दिशा में योगदान होगा। कुछ पंक्तियां निम्नानुसार हैं:-

बचपन में माँ चाहती, लाडलों
के पैर जल्दी बड़े हो जाएं।
पिता कहते बेटे का पैर बड़ा हो
जाए तो मित्र समझा जाए।
अब हमें होना है समझदार कि,
कार्बन फुटप्रिंट छोटा हो जाए।
यही है वसुंधरा की पुकार
कार्बन उत्सर्जन कम करते जाएं।

'कार्बन फुटप्रिंट' को कम करने के उपाय

- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल। इनसे प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन नहीं होता तथा ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है।
- पौधारोपण करना और वनों की कटाई को रोकना।
- पानी दुरुपयोग रोकना। एसी तथा कूलर पर कम निर्भरता रखकर कम से कम उपयोग करना ।
- एलईडी बल्ब का इस्तेमाल ।
- पुराने फ्रिज को बदलें क्योंकि इनके कंप्रेसर ज्यादा बिजली खा जाते हैं और ज्यादा 'कार्बन फुटप्रिंट' का कारण बन जाते हैं।
- सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल, काम और नौकरी पर जाते समय, अलग-अलग ना जाते हुए कारपूल का उपयोग।
- वस्त्रों का पुर्ननवीनीकरण और पुनर्चक्रण।
- मांस उत्पादनों का कम उपयोग ।
- खरीदी की आदतों को बदलना अर्थात ऐसे उत्पादन खरीदना, जिनके उत्पादन और परिवहन के लिए कम कार्बन उत्सर्जन होता है ।
- डिजिटाइलेशन पर अधिक जोर देना। डिजिटल बैंक को प्रोत्साहन देना।

'कार्बन फुटप्रिंट' का सबसे बड़ा कारण

व्यक्ति की 'यात्रा इच्छा' तथा घर में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरण है। अर्थात व्यक्ति के अधिकतर आदतें, (जिसमें खान-पान से लेकर वस्त्रों तक को शामिल किया गया है) उसके 'कार्बन फुटप्रिंट' का कारण बन जाते हैं। भोजन, उपभोग की वस्तुऐं, परिवहन एवं घरेलू ऊर्जा खपत, 'कार्बन फुटप्रिंट' के प्रमुख कारणों में से एक होता है। पर्यावरण एनजीओ 'द नेचर कंजर्वेंसी' का अनुमान है कि ग्रह पर प्रत्येक निवासी हर साल औसतन लगभग 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, जबकि अमेरिका में यह मात्रा प्रति व्यक्ति और प्रतिवर्ष 4 गुना से ज्यादा है। हम सबको 2050 तक 'कार्बन फुटप्रिंट' को प्रतिवर्ष 2 टन से कम करने की जरूरत है।

वृक्षारोपण : पृथ्वी की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

तरुण मेहरा
दैनिक अनोखा तीर
संवाददाता सेमरी हरचंद

पृथ्वी अपने समृद्धि, स्वास्थ्य और समता के लिए वृक्षों की आवश्यकता है। वृक्षारोपण न केवल वन्यजीवन के लिए बल्कि मानवता के लिए भी लाभदायक है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हम सभी को साझा करनी चाहिए। वृक्षारोपण का महत्व वर्तमान समय में अनपेक्षित रूप से बढ़ गया है। वन्यजीवन की कमी, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और भूमि संरचना में बदलाव के कारण हमें वृक्षारोपण के महत्व को समझना और इसमें योगदान करना जरूरी है। वृक्षारोपण का प्राकृतिक लाभ असीमित है। ये पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ रखते हैं, ऑक्सीजन के निर्माण में मदद करते हैं, जल संचयन को बढ़ाते हैं और जलवायु को शांत रखते हैं। वृक्षारोपण ने जीवन की उत्पत्ति और उसके संघर्ष में आराम प्रदान किया है।

वृक्षारोपण न केवल प्राकृतिक वातावरण को सुधारता है, बल्कि यह मानव समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण से जीवन के बेहतर गुणवत्ता के साथ-साथ स्थानीय आर्थिक विकास का समर्थन किया जा सकता है। यह स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है और उन्हें जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वृक्षारोपण के महत्व को लोगों को समझाने के लिए सामाजिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण रोल है। सरकार, संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर वृक्षारोपण के लिए अधिक से अधिक अभियानों का समर्थन करना चाहिए। इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा मानकर, हम सभी इसमें योगदान कर सकते हैं। वृक्षारोपण भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्या 200 ट्रिलियन डॉलर से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है?

यह अनुमान लगाया गया है कि अनियंत्रित ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद से प्रति वर्ष 23 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान कर सकती है।

एक नई रिपोर्ट का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया के कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए 196 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की लागत आ सकती है, कई देशों ने समाज को नष्ट करने वाली ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इस समय सीमा का पालन करने का वादा किया है। विडंबना यह है कि दुनिया की नेट-शून्य प्रतिज्ञाओं का अभी तक हार्ड कैश, या यहां तक कि हार्ड कैश के वादों का पालन नहीं किया गया है, जो उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक है।

एक कार्यशील मानव सभ्यता के संरक्षण पर आप क्या कीमत लगाएंगे? क्या 200 ट्रिलियन डॉलर से यह लगभग पूरा हो जाएगा? क्या यह भी एक सौदा हो सकता है?

ब्लूमबर्ग एनईएफ, ब्लूमबर्ग की हरित-ऊर्जा अनुसंधान टीम ने इस सप्ताह एक नई रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2050 तक दुनिया के कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए 196 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की लागत आ सकती है, जैसा कि कई देशों ने समाज को नष्ट करने वाली ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए करने का वादा किया है। यह जानकर शायद आपको कोई झटका नहीं लगेगा कि दुनिया की नेट-शून्य प्रतिज्ञाओं को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक हार्ड कैश, या यहां तक कि हार्ड कैश के वादों का अभी तक पालन नहीं किया गया है।

बीएनईएफ का सुझाव है कि अगर हमें 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने की कोई उम्मीद है तो 2030 तक वार्षिक हरित निवेश को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 6.9 ट्रिलियन डॉलर करना होगा। इसमें सरकारें, व्यवसाय और उपभोक्ता शामिल होंगे जो दुनिया के अधिकांश गैस-चालित वाहनों के बेड़े को इलेक्ट्रिक के लिए बदल देंगे। उन वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना और जीवाश्म ईंधन से चलने वाली ऊर्जा को पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा से बदलना, उन सभी को जोड़ने के लिए नए ग्रिड बनाना।

बीएनईएफ विश्लेषक निलुशी करुणारत्ने ने एक रिपोर्ट में लिखा है, 'जलवायु परिवर्तन के वास्तविक प्रभाव दिन-ब-दिन अधिक वास्तविक होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में सेंध लगाने की खिड़की बंद हो रही है।' 'लेकिन अभी भी सार्थक बदलाव का अवसर है।'

बीएनईएफ का अनुमान वास्तव में मैकिन्से के अनुमान की तुलना में निचले स्तर पर है कि समाज को जीवाश्म ईंधन से दूर करने के लिए 2021 और 2050 के बीच औसत वार्षिक खर्च 9.2 ट्रिलियन डॉलर या 275 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। बीएनईएफ के समान, मैकिन्से ने भी चेतावनी दी कि अगले 15 वर्षों के भीतर सबसे अधिक खर्च होगा। ये संख्याएं भले ही चौंकाने वाली बड़ी लगें, लेकिन कुछ न करने की संभावित कीमत की तुलना में ये न्यूनतम हैं।

$23 ट्रिलियन : वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद से प्रति वर्ष, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठंडी दुनिया की तुलना में 7 प्रतिशत छोटी है और विकसित अर्थव्यवस्थाएँ संभवतः 10 प्रतिशत छोटी हैं। ऐसे उपायों से 27 वर्षों में 200 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना अपेक्षाकृत सस्ता लगता है।

एसएंडपी ग्लोबल ने अनुमान लगाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इसका मतलब प्रति वर्ष केवल 13 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है - फिर भी हम उनसे बचने के लिए जो 7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे, उससे भी अधिक। और ये नुकसान विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में तेजी से बढ़ते देशों पर भारी पड़ेगा, जिसमें दक्षिण एशिया को सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत, मध्य एशिया को 7 प्रतिशत और उप-सहारा अफ्रीका को 6 प्रतिशत का नुकसान होगा।

2050 तक शून्य का लक्ष्य कोई मनमाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने की हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है, जिसके परे ग्रह की रहने की क्षमता को नुकसान तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल हम वार्मिंग के 3C तक पहुंचने की राह पर हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इससे ग्रह का बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रह जाएगा।

बेरहमी से बर्बाद हो रहा हिमालय

■ कुलभूषण उपमन्यु

इन दिनों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश जैसे देश के उत्तरी राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आम आबादी समेत वैज्ञानिक और राजनेता तक, सब जानते हैं कि इसकी बुनियादी वजह कथित विकास की खातिर अपेक्षाकृत नवजात पर्वत हिमालय के साथ की गई बेहूदी छेड़-छाड़ है। तो क्या पूंजी के सामने हम अपना वर्तमान और भविष्य लुटाने में लगे रहेंगे? क्या होंगे इसके नतीजे ?

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन ने अपना क्रुर चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में 200 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। यही हाल उत्तराखंड का है। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर में जान-माल की पर्यावरण डाइजेस्ट अप्रत्याशित तबाही दिल दहला देने वाली है। मृतकों की संख्या 31 हो गई थी। जगह-जगह लोग प्रकृति के क्रोध के शिकार होकर असहाय अनुभव कर रहे हैं। सरकार मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, किन्तु साल-दर-साल बढ़ती बाढ़ की विभीषिका कई सवाल खड़े कर रही है।

जलवायु परिवर्तन के असर की भविष्यवाणी तो कई सालों से की जा रही है, लेकिन हिमालय जैसे नाजुक पर्वतीय क्षेत्र में उचित सावधानियां नहीं बरती गई हैं। सैंकड़ों पर्यटक जगह-जगह फंसे पड़े हैं। सरकार भी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्यवाही कर रही है, किन्तु बरसात में पर्यटन को किस तरह दिशा-निर्देशित किया जाना चाहिए इस बात की कमी खलती है। पर्यटन सूचना केन्द्रों का नेटवर्क सक्रिय होना चाहिए जो बरसात के खतरों से अवगत करवाए। मंडी में हुई तबाही के पीछे लारजी और पंडोह बांधों से अचानक छोड़ा गया पानी भी जिम्मेदार माना जा रहा है।

बांधों के निर्माण के समय बाढ़ नियंत्रण में बांधों की भूमिका का काफी प्रचार किया जाता रहा है, किन्तु देखने में उल्टा ही आ रहा है। बांधों से अचानक और बड़ी मात्रा में छोड़ा जाने वाला पानी ही अप्रत्याशित बाढ़ का कारण बनता जा रहा है। बरसात से पहले बांधों में बाढ़ का पानी रोका जा सके इसके लिए बांधों को खाली रखा जाना चाहिए, किन्तु अधिक से अधिक बिजली पैदा करने के लिए बांध भरे ही रहते हैं। बरसात आने पर पानी जब बांध के लिए खतरा पैदा करने के स्तर तक पहुंचने लगता है तो अचानक इतना पानी छोड़ दिया जाता है जितना शायद बिना बांध के आई बाढ़ में भी न आता। इन मुद्दों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बांध प्रशासन को निर्देशित किया जाना चाहिए। बांधों से बाढ़ नियन्त्रण की भूमिका को सक्रिय किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी गडबड सड़क निर्माण में हो रही लापरवाही भी हो रही है। निर्माण कार्य में निकलने वाले मलबे को निर्धारित स्थानों, डंपिंग स्थलों में न फेंककर यहाँ वहां फेंक दिया जाता है और वही मलबा बाढ़ को कई गुना बढ़ाने का कारण बन जाता है। मलबा जब एक बार नीचे ढलानों पर खिसकना शुरू होता है तो अपने साथ और मलबा बटोरता जाता है, जिससे भारी तबाही मचती है। नदी-नालों में जब यह मलबा पहुंचता है तो नदी का तल ऊपर उठ जाता है और वह क्षेत्र जो पहले कभी बाढ़ की जद में नहीं आए थे वे भी अब बाढ़ की जद में आ जाते हैं।

सड़क निर्माण में जल निकासी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। सड़क किनारे बनाई गई नालियों से जल इकट्ठा होकर कहीं एक जगह छोड़ दिया जाता है जो भू-कटाव बढ़ाने का कारण बनता है। सड़क निर्माण विधिवत पर्वतीय दृष्टिकोण से कट एंड फिल तकनीक से किया जाना चाहिए। पहाड़ों में सड़क के विकल्पों पर भी सोचा जाना चाहिए। सड़क तो जीवन रेखा है, किन्तु जीवन-रेखा यदि जीवन को ही लीलने लग जाए तो सोचना पड़ेगा कि गडबड कहां हो रही है। सड़क के विकल्प के रूप में मुख्य मार्गों से लिंक सडकों की बजाय उन्नत तकनीक के 'रज्जू मार्ग' (रोप वे) बनाए जा सकते हैं, किन्तु इस दिशा में सरकारों ने सोचना ही शुरू नहीं किया है। हां, पर्यटन आकर्षण के रूप में कुछ-कुछ जगहों पर 'रज्जू मार्ग' बने हैं। उनके अनुभवों से सस्ती और टिकाऊ यातायात सुविधा निर्माण की जा सकती है। फिलहाल जब यह बात उजागर हो गई है कि मलबा डंपिंग की भूमिका भूस्खलन बढाने में मुख्य है तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर जहां-जहां नुकसान हुआ है वहां तकनीकी जांच करवाई जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में चीफ विजिलेंस अफसर को जाँच के लिए कहना चाहिए।

वर्ष 1994 में भागीरथी के तट पर जब टिहरी बांध विरोधी आन्दोलन चल रहा था, तब हिमालय बचाओ आन्दोलन का घोषणा पत्र जारी हुआ था। इसकी मुख्य मांग थी कि हिमालय की नाजुक परिस्थिति के मद्देनजर विकास की विशेष प्रकृति- मित्र योजना बनाई जाए। योजना आयोग द्वारा डॉ. एसजेड कासिम की अध्यक्षता में बनाई गई विशेष समिति ने 1992 में इसी आशय की रिपोर्ट जारी की थी, किन्तु उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लोग लगातार विकास के नाम पर चल रही अंधी दौड़ के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, किन्तु सरकारों और तकनीकी योजना निर्माताओं के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। एक अच्छा बहाना इन लोगों को मिल जाता है कि प्रकृति के आगे हम क्या कर सकते हैं, किन्तु इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि प्रकृति को इतना मजबूर करने का आपको क्या हक है कि प्रकृति बदला लेने पर उतारू हो जाए। हालांकि इस विषय पर चर्चा तो सरकारी क्षेत्रों में चलती रहती है, वर्तमान सरकार में भी नीति आयोग द्वारा हिमालयी क्षेत्र में विकास की दिशा तय करने के लिए 'रीजनल कौंसिल' का गठन किया गया है, किन्तु अभी तक इस संस्था की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है।

अब समय है कि सब नींद से जागें और हिमालय में विकास की गतिविधियों को प्रकृति मित्र दिशा देने का प्रयास करें। हमें सोचना होगा कि हिमालय में होने वाली कोई भी पर्यावरण विरोधी कार्यवाही पूरे देश के लिए हिमालय द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं से वंचित करने वाली और घातक साबित होगी।

बाढ़ से बचाव और राहत के लिए ठोस रणनीति आवश्यक

> प्रकृति के साथ निरंतर की गई छेड़छाड़ के परिणास्वरुप आज हमें ऋतु परिवर्तन के रुप में आए दिन हमें अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें बाढ़ प्रमुख है। भारत में हर वर्ष वर्षाकाल में कई राज्यों में बाढ़ की भयावहता देखने को मिलती है। इस जल प्रलय से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। हजारों लोगों को पलायन करना पड़ता है और अनेक जिन्दगियां काल के गाल में समा जाती हैं। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, परंतु इसके बचाव के उपाय किए जा सकते हैं।

प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ मानव जीवन के लिए एक विभीषिका है। जल प्रलय के रूप में प्रकृति का यह रौद्र रूप है। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य सहित सभी जीवों के जीवन के लिए जल तत्व आवश्यक बताया गया है। वर्षा की कमी से सूखा और अकाल की स्थिति बनती है, वहीं इसकी अधिकता बाढ़ के कारण रूप में हमारे सामने आती है।

श्रीराम माहेश्वरी
पर्यावरणविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार

भारत में हर वर्ष वर्षाकाल में कई राज्यों में बाढ़ की भयावहता देखने को मिलती है। इस जल प्रलय से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। हजारों लोगों को पलायन करना पड़ता है और अनेक जिन्दगियां काल के गाल में समा जाती हैं। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, परंतु इसके बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। राहत की व्यवस्था की जा सकती है। आपदा प्रभावित यूएन के वैश्विक 10 देशों की सूची में भारत भी शामिल है।

आपदा प्रभावित यूएन के वैश्विक 10 देशों की सूची में भारत का नाम भी शामिल है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरे क्रम में भारत।

अमेरिका और चीन के बाद तीसरे क्रम पर भारत है, जहां आपदा आने की घटनाएं होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं में विश्व भर में वृद्धि हुई है। विश्व के अनेक देशों में इस दौरान 7 हजार से अधिक आपदाएं आ चुकी हैं। 20 वर्षों के मध्य भारत में सवा तीन सौ से अधिक इस तरह की आपदाएं आई हैं।

देश में बाढ़ आने के कई कारण देखे गए हैं। इनमें प्रमुख हैं- अतिवृष्टि, वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, बांधों से पानी छोड़ा जाना, नदियों के जल मार्ग का अवरोध होना, जल प्रवाह मार्ग में प्रदूषण, रेत मिट्टी और गाद जमा होने से नदियों की गहराई कम होना, पुल, बांध और तटबंधों का टूटना तथा जल मार्ग की चौड़ाई कम होना। इनके अलावा प्राकृतिक कारण भी हैं जैसे- चक्रवात, तूफान, सुनामी, भूकंप आदि। देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को यदि देखा जाए तो उत्तरप्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे तीन राज्यों में आधे से अधिक बाढ़ का प्रकोप रहता है। इन तीन राज्यों की करीब चार करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सदैव बाढ़ का खतरा बना रहता है। हालांकि हर साल बाढ़ का प्रभाव एक जैसा नहीं रहता। कभी कम और कभी ज्यादा प्रकोप रहता है।

बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों को केंद्रीय जल आयोग ने चार भागों में बांटा है। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, दूसरा, उत्तर पश्चिमी नदी क्षेत्र, तीसरा, गंगा नदी क्षेत्र तथा चौथा दक्कन नदी क्षेत्र है। बाढ़ का ज्यादा प्रकोप ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण है- ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा मार्ग बदलना, तटों के ऊपर पानी बहना, भूस्खलन होना तथा नालों के मार्ग में रुकावट आना। बराक, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के प्रवाह तटबंधों के ऊपर होने के कारण ही असम में भीषण बाढ़ आती है।

गंगा नदी क्षेत्र के उत्तरी इलाकों में बाढ़ की पुनरावृत्ति होती रहती है। उत्तरप्रदेश में घाघरा, शारदा, राप्ती तथा बिहार में बागमती कोसी, बूढ़ी गंडक तथा सहायक नदियों के कारण बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने का कारण है- भागीरथी, अजय, दामोदर और महानंदा नदियां। इन नदियों की कम चौड़ाई के कारण बाढ़ का विकराल रूप हो जाता है। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नालों में रुकावट के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों के बड़े भूभाग पर बाढ़ का पानी बना रहता है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है।

जम्मू कश्मीर में चिनाब, झेलम तथा सहायक नदियों के कारण बाढ़ आती है। वहीं उड़ीसा में ब्राह्मणी, महानदी और वैतरणी नदियां बाढ़ का कारण बनती हैं। इसके विपरीत मध्यभारत और दक्षिण के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति न्यूनतम है। नर्मदा और ताप्ती नदी के पानी से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। निकासी की समस्या के कारण कृष्णा और गोदावरी नदियों के प्रवाह से पूर्वी तट के क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस तरह वर्षाकाल में देश के लगभग आधे राज्य बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं और बड़ी आबादी इस त्रासदी से प्रभावित होती है।

भारी बारिश इसके कारण पिछले दिनों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आई। इससे 65 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अनेक लोग लापता हो गए। प्रभावित 28 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। अभी भी कई राज्यों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। विचारणीय तथ्य यह है कि बाढ़ जैसी आपदा से हम कैसे बचाव करें। बाढ़ की क्षति को कम करने के लिए हमें संरचनागत उपाय तथा गैर संरचनागत उपाय, पूर्वानुमान आंकलन और विश्लेषण की आवश्यकता है। पूर्वानुमान के अंतर्गत वर्षा होने, उसकी अवधि, उसकी तीव्रता तथा वितरण की भविष्यवाणी समय पर करने की व्यवस्था करना चाहिए। इस प्रक्रिया में बादलों की गहनता का भी अध्ययन शामिल करना चाहिए। दूसरे, उपग्रह आधारित दूर संवेदन तकनीक के द्वारा हमें पूर्वानुमान की सूचनाओं को जिलों के नेटवर्क केंद्रों पर समय पर साझा करना चाहिए, जिससे कि वे प्रभावित क्षेत्रों में चेतावनी उद्घोषणा कर सकें। तीसरे स्तर पर हमें पिछली वर्षा और बाढ़ का आंकलन कर विश्लेषण करना चाहिए। इसी आधार पर भावी योजनाएं और बचाव की रणनीति बनाना चाहिए। सेटेलाइट तकनीक से हमें ग्लेशियर पिघलने की स्थिति को मापना तथा हिम आच्छादन की स्थिति का अध्ययन करना भी उचित होगा।

संरचनागत उपायों के अंतर्गत हमें नदियों के जल मार्गों की रुकावट दूर करना चाहिए। बांधों में जल निकासी चैनलों का निर्माण, भूमि कटाव रोकने हेतु निर्माण कार्य और मरम्मत तथा जलमार्ग की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के कार्य आवश्यक होंगे। इन उपायों से हम बाढ़ के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में आवश्यकतानुसार रक्षकों की भर्ती करके प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें समय पूर्व नियुक्त कर सकते हैं। प्रशिक्षित जवानों की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती है। हमें इस कमी को दूर करना होगा। इन उपायों से हम बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बड़ी आबादी को बचा सकते हैं और उन्हें समय पर राहत दे सकते हैं। इस हेतु हमें राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

Email : srmaheshwaribhopal@gmail.com

माई इंडिया माई लाइफ

दुनिया में मिशाल बन रहें जिनके काम

“भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एकेएएम डिवीजन के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस पर माई इंडिया माई लाइफ गोल्स अभियान शुरू किया। तब से यह पहल पर्यावरण के लिए जीवनशैली को मुख्यधारा में ला रही है, जो हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक विचार है। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए यह अभियान देश के नागरिकों को संविधान में निहित 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अभियान के साथ हमने लोगों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करने और लाइफ लक्ष्यों का पालन करने का संकल्प लेने के लिए भी जागृत किया। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक हमने पर्यावरण कार्यकर्ताओं ‘हरित योद्धाओं’ की कहानियाँ देखीं, जो न केवल प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए काम करते हैं, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी हैं। हम आज आजादी के अमृत महोत्सव अवसर पर कुछ ऐसे लोगों की कहानियों से आपको अवगत करा रहे हैं।”

पुलिस आरक्षक देवेन्द्र सूरा बन गया ट्री मैन ऑफ हरियाणा

देवेंदर सूरा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल हैं। एक एथलीट, दो बच्चों के पिता, अपने राज्य में वन क्षेत्र के नुकसान और जलवायु परिवर्तन को देखने के बाद पर्यावरणविद् बन गए, उन्होंने इसे अपने दम पर उलटने का फैसला किया। उनकी यात्रा 2011 में शुरू हुई जब उन्होंने सोनीपत में पेड़ लगाना शुरू किया। देवेंदर सूरा अपने स्वयंसेवकों की टीम (पर्यावरण मित्र) के साथ भारतीय प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर साल 30-40 हजार पेड़ लगाते हैं। अपने पिता द्वारा परिवार का सारा खर्च उठाने के बावजूद, वह अपना पूरा वेतन वृक्षारोपण पर खर्च करते हैं। सिर्फ वेतन ही नहीं, वृक्षारोपण की अपनी यात्रा के दौरान देवेन्द्र ने 5 ऋण भी लिए हैं। जनता से जुड़ने और इस पहल को फैलाने के लिए देवेंद्र सूरा ने सोनीपत-गोहाना राजमार्ग के किनारे एक ‘जनता नर्सरी’ खोली है, जहां हर साल पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों के लगभग 25,000 पौधे मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाते हैं। यह 2020 में था जब देश में कोविड-19 महामारी आई थी, देवेंदर सूरा ने ‘ऑक्सीजन बैग’ नामक एक और पहल शुरू की, जहां उन्होंने अपने पर्यावरण मित्र के साथ ऑक्सीजन-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों पेड़ लगाना शुरू किया। देवेंदर सूरा न सिर्फ पेड़ लगाते हैं बल्कि उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं। वह पेड़ों पर रहता है और उनमें सांस लेता है। हालांकि उनका मानना है कि पर्यावरण को संरक्षित करना सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है।

Constantly active in the field of environmental protection

Bikrant Tiwary
Director, IMPCA Services Private Limited

Bikrant is passionately dedicated to making a positive impact on the world and preserving nature while also contributing to community development. With over 21 years of valuable work experience, his journey has been diverse and enriching. He spent 9 years working in the Insurance and Service sectors, where he gained insights into the corporate world. However, his transition to the social sector truly defined his purpose and sparked a transformation within him.Bikrant's dedication to philanthropy and Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives led him to serve as the National Head of GiveIndia, an online platform that mobilizes resources to support NGOs and corporates in their philanthropic endeavors. This role allowed him to create meaningful connections between corporations and impactful social projects, fostering large-scale positive change.In the past decade, Bikrant has been the driving force behind a well-known social enterprise in India. Under his leadership as Global CEO, over 17 million trees have been planted across India and beyond, aligning with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) and promoting a greener, sustainable future. An alumnus of IIM Calcutta, Bikrant holds a postgraduate degree in HR and Marketing. He further honed his skills with a few distinguished certificate programs at Harvard Business School, Boston.Through nature conservation, he envisions a future where indigenous communities thrive in harmony with nature.

Successfully planting over 17 million trees

Supriya Patil
Director, IMPCA Services PVT. LTD

Supriya is a dedicated environmentalist with a Master's degree in Environmental Science and sustainability. With a career spanning over a decade in the environment conservation space, she has been at the forefront of initiatives that prioritize both environmental protection and social equality. As the COO of a leading nature conservation organization in India, she led the organization in successfully planting over 17 million trees across India and Africa, demonstrating her commitment to nature-based initiatives on a large scale. Continuing her commitment to sustainability, Supriya joined the social enterprise IMPCA which develops large-scale nature-based livelihood programs projects focusing on building strong economic opportunities for the farmers of India. With a resolute determination, Supriya has set her sights on planting millions of trees to tackle carbon emissions, create livelihood opportunities for rural communities, and enhance wildlife habitats and biodiversity. She envisions empowering numerous villages by creating self-reliant rural micro-entrepreneurs, leading to improved lifestyles and sustainable income opportunities.

मुंबई के समुद्र प्रेमी अफ़रोज शाह

मुंबई के एक वकील अफरोज शाह जो समुद्र प्रेमी हैं। जिन्होंने वर्सोवा समुद्र तट से 5 मिलियन किलोग्राम कचरा साफ करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस मिशन की शुरुआत 2015 में की थी। बाद में यह नागरिकों के बीच सबसे बड़ी सफाई क्रांति बन गई और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट सफाई मिशन बन गया। यह एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने आसपास के वातावरण को साफ करने के लिए प्रेरित किया है। 50 लाख किलोग्राम कचरा साफ करने में 85 सप्ताह लगे। 2016 में मुंबई के वर्सोवा बीच की सफाई का नेतृत्व करने के लिए शाह को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में नामित किया गया था। मुंबई में समुद्र तटों को साफ़ करने के अफरोज शाह के प्रयास से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विश्व स्तर पर स्वच्छ समुद्र अभियान शुरू किया।

A commendable initiative in the field of climate change

SANDEEP ROY CHOUDHURY
Director and Co Founder

Sandeep is a Director and a co-founder at VNV Advisory Services, a social enterprise working with communities & climate change. He heads VNV's ownership on low carbon social development projects such as sustainable agriculture, social forestry, clean cooking, rural energy access and waste management. His work encompasses over 5 million rural households across the South Asia region(India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal & Myanmar) and over 50 NGO's and implementation partners.

He is recently involved in spearheading VNV's efforts towards rural water access, crop storage, agri-linkages and working with models of innovative financing through existing climate finance mechanisms to achieve scalability. He is also on the board of numerous non – profits working on climate-related projects including World-view International Foundation, Bangladesh Bondhu Foundation & Environment Protection Center Nepal.

Sandeep has over 16 years of industry experience and is a Salzburg Global fellow. He is also a director at “Carbon Initiative forum“, a non profit organisation working on climate change awareness and co-chair of ICROA(International Carbon Reduction & Offset Alliance).

Proficient in effective action planning

SHREYA DUTTA
Head of Programme Relations

Shreya heads the Program Relations team at VNV Advisory, responsible for overseeing the implementation and management of VNV projects across various thematic areas. With a degree in Literature from Lady Shri Ram College, New Delhi and a masters diploma in Human Rights from Delhi University. Shreya has worn many hats during her career of 18 years. Her interests in connecting livelihoods and communities have been a driving force through her career. She has worked in human resource management, education, project management, and co-founded & run a successful business before joining VNV in her current role. Self-driven, articulate and equipped with an entrepreneurial mindset, Shreya has been instrumental in building up the Program Relations team over the last two years. She, along with the team, focuses on ensuring seamless execution of projects, as well as overseeing day to day project operations, along with investor management for the VNV project portfolio. She enjoys collaborating with colleagues across verticals at VNV, and actively seeks out new things to learn.

भारत के वन पुरुष जिसने एक एक पौधा लगा कर खड़ा किया वन

यह जुनून और दृढ़ता की कहानी है। अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर किसी कार्य में जुट जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। आज हमारे सामने इसके उदाहरण के तौर पर जादव मोलाई है जिन्होंने एक-एक पौधा लगाकर घना जंगल तैयार कर दिया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि यह कहानी है पद्मश्री पुरस्कार विजेता जादव मोलाई पायेंग की। 1979 में एक 16 वर्षीय लड़के ने प्रतिदिन एक पौधा लगाना शुरू किया। आज प्रतिदिन एक पेड़ लगाने की उस प्रथा के साथ, उन्होंने अकेले ही 550 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल तैयार कर लिया है। यह वास्तव में एक व्यक्ति की शक्ति है जिसे द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।

वाराणसी में गंगा के तटों को साफ करते हैं राजेश शुक्ला

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोग अलग-अलग मोर्चों पर अपनी सेवाएं देते है। इसी में शामिल है वाराणसी के राजेश शुक्ला। श्री शुक्ला प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ घाटों के किनारे गंगा के एक हिस्से को साफ करते हैं। श्री शुक्ला अपनी टीम के साथ दशाश्वमेध घाट की सफाई करते हुए प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े और पॉलिथीन सहित कचरा इकट्ठा करते हैं। वे एकत्रित कचरे को घाट की सीढ़ियों पर रख देते हैं, जिसे बाद में सफाई कर्मचारियों की एक टीम उठाकर डंपिंग यार्ड में ले जाती है। यह हरियाली का पोषण करता है और पर्यावरण की रक्षा करता है।

तपती धरती संपादक मण्डल

सलाहकार संपादक: गौरीशंकर मुकाती
संपादक: प्रहलाद शर्मा
प्रबंध संपादक: श्रीराम माहेश्वरी, भोपाल
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि: संदीप राय चौधरी, सिंगापुर
राष्ट्रीय प्रतिनिधि: विक्रांत तिवारी, मुम्बई